an>

title: Need to improve the financial condition of East Delhi Municipal Corporation.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दिल्ली क्षेत्र हमारे भारत की राजधानी भी है। आपने कई बार बीच में टीवी पर देखा होगा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से हड़तालें हुई और दिल्ली की सड़कों पर कचरे का अंबार लगाया गया। उस पीड़ा को कहीं न कहीं राज्य सरकारों द्वारा महसूस नहीं किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली एक केन्द्र शासित प्रदेश है। इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2012 में केन्द्र सकार द्वारा निर्णय लिया गया, जब यूपीए की गवर्नमैंट थी, कांग्रेस की गवर्नमैंट थी और राज्य में भी कांग्रेस की गवर्नमैंट थी। उस समय एक से तीन नगर निगम अलग किए गए। उस समय यह आशंका भी जताई गई थी कि इसमें राजस्व का वितरण अगर सही नहीं हुआ तो कई क्षेत्रों में विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उस वक्त मैं राजनीति में तो नहीं था, लेकिन पता नहीं उस निर्णय को उस गवर्नमैंट ने अपने किस लाभ से लिया या क्या हुआ, पर आज हालात इतने गंभीर हैं कि मैं उन सफाई कर्मचारियों के घरों में जाकर उनसे मिला हूँ। दीवाली जैसे त्योहारों में दीवाली नहीं मनाई गई, छः-आठ महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला और जब राज्य सरकार को कहा गया कि इस नगर निगम को वह धन आबंटित किया जाए जिसका उनको हक है, तो राज्य सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया कि आप पी.एम. मोदी से मांग लो क्योंकि वहाँ आपकी ही पार्टी की सरकार है। यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे उत्तर मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से कचरे का अंबार लग रहा है। उनको जल्द से जल्द वेतन मिले, नगर निगमों को उनका आबंटित धन मिले, ताकि दिल्ली का क्षेत्र स्वच्छ रहे और स्वच्छ भारत की जो संकल्पना हमारे प्रधान मंत्री जी की है, वह हम बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाएं। मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, *m0श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री महेश गिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।